(ख) यदि हां, तो इन कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से उन खानों को अपने आधिपत्य में लेने का अनुरोध किया है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) से (घ) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् केन्द्र सरकार के निदेश पर बिहार सरकार ने निजी पार्टियों द्वारा धारित 54 पट्टे रद्द कर दिए हैं तथा वे पट्टे सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को मंजूर किए जा चुके हैं ।

तमिलनाडु में हिन्दी विरोधी आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पेंशन

*126. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तमिलनाडु में पिछले हिन्दी विरोधी आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पेंशन दी गई है ,

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और

(ग) उन्हें पेंशन के रूप में प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) :(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1480

(ग) उन व्यक्तियों जिन्होंने अपना बलिदान दिया था उनके आश्रितों को प्रत्येक मामले में 100— रुपये प्रति माह अथवा 1200 ।—रुपये प्रति वर्ष और जिन्होंने आन्दोलन के सम्बन्ध में जेल काटी थी उनमें प्रत्येक को 751 —रुपये प्रति माह अथवा 900 ।— रुपये प्रति वर्ष स्वीकृत मामलों के सम्बन्ध में वार्षिक देयता 13,34,700 रुपये हैं ।

Nellethurai Hydro Electric Project

*134 SHRI C H MOHAMED KOYA Will the Minister of ENERGY be pleased to state.

(a) whether the Government of Kerala have raised objection against the sanction issued to the Government of Tamil Nadu to take up the Nellethurai Hydro Electric Project; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K C PANT) (a) Yes, Sir

(b) The sanction to the project is without prejudice to Kerala's interest in the use of Cauvery waters

Recommendations of Committee on Small Scale Industries

*135 SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government have implemented the recommendations submitted by the Nayak Committee—1975 for development of small scale industries, and

(b) if so, outline thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A P SHARMA) (a) and (b) The Nayak Committee Report on the Re-structuring of State Level Organisations concerned with the development of Small Scale Industries was considered at the meeting of the Small Scale Industries Board in September, 1975, and the recommendations of the Committee were, by and large, approved